केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

# जलांश

खंड 6 अंक 3 अक्तूबर -2023

**श्री कुशविंदर वोहरा**
**अध्यक्ष, के ज आ**

## संदेश

जैसे ही हम सितंबर माह पर विचार करते हैं, मुझे केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की कुछ उल्लेखनीय गतिविधियां और उपलब्धियां साझा करते हुए खुशी हो रही है।

जलशक्ति मंत्रालय के डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने 14 से 15 सितंबर, 2023 तक जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आरआईसी) में बांध सुरक्षा (आईसीडीएस) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बड़े बांधों के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, हमारी भागीदारी का उद्देश्य 6,000 से अधिक बांधों जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक की है की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाना और विशेषज्ञता का योगदान करना है, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हमारे देश की समृद्धि में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए सम्मेलन का उद्घाटन किया।

माननीय उपराष्ट्रपति ने बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर का भी अनावरण किया। सीडब्ल्यूसी देश भर के बड़े बांधों के लिए; राज्य सरकारों/पीएसयू द्वारा प्रदान की गई जानकारी संकलित करता है और राष्ट्रीय बड़े बांध रजिस्टर (एनआरएलडी) के रूप में उनका प्रबंधन करता है।

सीडब्ल्यूसी, जो जल संसाधन विकास और प्रबंधन में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, ने इस माह के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और मंत्रालयों के साथ कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ये सहयोग देश भर में जल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। प्रमुख रूप से, धार जिले में करम मध्यम सिंचाई परियोजना की डिजाइन समीक्षा परामर्श के लिए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।सीडब्ल्यूसी ने जल संसाधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सीडब्ल्यूसी द्वारा किए जा रहे कार्यों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए कार्यों में तालमेल बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन/ सिंचाई/जल शक्ति विभाग के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है।

राज्य में संपूर्ण जल क्षेत्र की जरूरतों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक आधार पर राज्य सरकारों के साथ सबसे पहले मेरे स्तर पर और दूसरी, कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में सीजीडब्ल्यूबी के सहयोग से त्रैमासिक आधार पर सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर विचार-विमर्श आयोजित किया जाएगा।

इस संबंध में, मैंने क्रमशः 01.09.2023 और 08.09.2023 को बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी के साथ वार्षिक विचार-विमर्श बैठकें आयोजित कीं। बिहार सरकार की ओर से, श्री चैतन्य प्रसाद, एसीएस, डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार ने सीडब्ल्यूसी के साथ हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

इसके अलावा, सीडब्ल्यूसी ने मेरे और महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी, श्री दीपक कपूर के साथ वार्षिक बातचीत बैठकों में सार्वजनिक जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण और जल संसाधन विकास से संबंधित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय जल अकादमी के माध्यम से महाराष्ट्र इंजीनियरिंग प्रशिक्षण अकादमी के साथ सहयोग बढ़ाया।

'सिंचाई जनगणना' योजना के तहत प्रमुख और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं की पहली जनगणना आयोजित करने के लिए लघु सिंचाई (सांख्यिकी) विंग और सीडब्ल्यूसी के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी एमएमआई परियोजनाओं की जनगणना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक है।जल शक्ति मंत्रालय ने हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। हाइब्रिड मोड में आयोजित पहली बैठक में विभिन्न प्रमुख संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी देखी गई, जो प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस महीने, हम दो महत्वपूर्ण पहलों- हिंदी पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में, हमने राजभाषा (हिंदी) में काम करने के लिए उत्साह बढ़ाने और उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए रूपांकित विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान अद्वितीय उत्साह के साथ मनाया गया क्योंकि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित स्वच्छता अभियानों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस सामूहिक प्रयास ने न केवल स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, बल्कि स्वच्छता के महान उद्देश्य के प्रति सीडब्ल्यूसी समुदाय की एकता और समर्पण को भी प्रदर्शित किया।

कुल मिलाकर सितंबर 2023 का महीना विभिन्न हितधारकों के साथ व्यस्तताओं से भरा रहा, जिसके आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे।

आगामी संस्करणों में, मैं सीडब्ल्यूसी द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में अधिक जानकारी साझा करूंगा।

# विषयसूची


### एनडीएसए और डीआरआईपी

- बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएस) 2023
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों के साथ बैठक

### परियोजना के संबंध में बैठक

- वियना, ऑस्ट्रिया में किशनगंगा और रतले जल-विद्युत परियोजना (एचईपी) के मामले में तटस्थ विशेषज्ञ की दूसरी बैठक
- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना,रेणुकाजी बांध परियोजना और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के अद्यतनीकरण की स्थिति
- पुनात्सांगछू-। एचईपी (6x200 मेगावाट) भूटान, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की 31वीं तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) (चरण । और ।।) की बैठक
- मयूरक्षी बांध परियोजना और फुबरी बांध की लागत हिस्सेदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समिति की दूसरी बैठक

### सीडब्ल्यूसी की अन्य गतिविधियाँ

- हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन हेतु समिति की पहली बैठक
- केंद्रीय जल आयोग और मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।
- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ वार्षिक संवाद बैठक
- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ वार्षिक संवाद बैठक
- स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट लैब (एसएलसीआर) पर संयुक्त संचालन समिति (जेएससी)
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की 5वीं बैठक
- प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओंकी पहली जनगणना के संचालन के लिए एमआई स्टेट विंग, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर और केंद्रीय जल आयोग के बीच समझौता ज्ञापन
- सिंचाई जनगणना योजना के तहत 7वीं एमआई जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना, एमएमआई परियोजनाओं की पहली जनगणना और झरनों की पहली जनगणना के लिए अनुसूचियों और परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना
- अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने अध्यक्ष, पीसीटीए और आईसीआईडी के उपाध्यक्षों के साथ बैठक में भाग लिया
- आईसीआईडी की 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक (आईईसी) की तैयारी के लिए गठित उप-समितियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करें।
- देश में बाढ़ की स्थिति - सितम्बर 2023
- 30.09.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति


# एनडीएसए और डीआरआईपी

## अंतर्राष्ट्रीय, बांध सुरक्षा पर सम्मेलन (आईसीडीएस) 2023

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने बांध सुरक्षा (आईसीडीएस) 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- ।। और ।।। के तहत 14-15 सितंबर 2023 के दौरान जयपुर में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। सम्मेलन "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सुरक्षित बांध" विषय पर आधारित था। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए), राजस्थान जल संसाधन विभाग, एमएनआईटी जयपुर, वैपकोस लिमिटेड, विश्व बैंक और एआईआईबी आदि के सहयोग से भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय के डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा किया गया था।

सम्मेलन; बांध सुरक्षा के क्षेत्र में विचारों का आदान-प्रदान करने, अनुभव साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और पेशेवरों को एक साथ लाया है। केंद्रीय सरकार संगठनों, राज्य सरकार संगठनों, सीपीएसयू, एसपीएसयू, बांध मालिकों, तकनीकी संस्थानों, बांध सुरक्षा विशेषज्ञों, उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा विशेषज्ञों से 130 से अधिक तकनीकी कागजात और सार प्राप्त हुए हैं। इस सम्मेलन में लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 51 वक्ताओं ने तकनीकी और औद्योगिक सत्र में अपनी मौखिक प्रस्तुति दी। सम्मेलन के दौरान पोस्टर फॉर्म में 15 तकनीकी पेपर भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, 45 औद्योगिक, राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सम्मेलन के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी में अपने उत्पादों, उपकरण, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का प्रदर्शन किया।दो दिवसीय सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और 8 विषय शामिल थे, जिन्हें 6 तकनीकी और 2 औद्योगिक सत्रों में विभाजित किया गया था। विषय थे:

1. बांध सुरक्षा प्रबंधन और शासन में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अभ्यास
2. बांध स्वास्थ्य आकलन (औद्योगिक सत्र)
3. बांध पुनर्वास पर सर्वोत्तम अभ्यास: केस स्टडीज
4. जलाशय तलछट प्रबंधन
5. संचालन, रखरखाव एवं आपातकालीन प्रबंधन
6.बांध की विफलताओं और बांध की घटनाओं से सबक
7. जोखिम मूल्यांकन
8. बांध पुनर्वास तकनीक एवं सामग्री (औद्योगिक सत्र)

## बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों के साथ बैठक

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में 27.09.2023 को सुबह 10:00 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, विभिन्न राज्यों के डब्ल्यूआरडी के साथ अग्रलिखित एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श हुआ:

- बांध सुरक्षा के लिए समर्पित ओ एंड एम बजट।
- राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) के नियमित सेट-अप की स्थापना। एसडीएसओ में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती।
- राज्य में गैर-निर्दिष्ट बांधों का डेटाबेस तैयार करना।

# परियोजना के संबंध में बैठक

## वियना, ऑस्ट्रिया में किशनगंगा और रतले एचईपी के मामले में तटस्थ विशेषज्ञ की दूसरी बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने आईडब्ल्यूटी मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने के लिए नियुक्त एनई की दूसरी बैठक में भाग लिया, जो 20-21 सितंबर, 2023 के दौरान वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई थी। श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, श्री एस.के.सिब्बल सदस्य, डी एंड आर, श्री नरेंद्र सिंह शेखावत, निदेशक और एम.एस.हर्षिता, उप निदेशक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव, डी ओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने किया। विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि के अनुच्छेद IX के तहत विशेष रूप से किशनगंगा और रतले एचईपी के संबंध में दोनों देशों के बीच तकनीकी मतभेद को संबोधित करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था।

## लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुकाजी बांध परियोजना और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के अद्यतनीकरण की स्थिति

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की समीक्षा, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए डीपीआर की स्थिति और रेणुकाजी बांध परियोजना की समीक्षा के लिए बैठक में भाग लिया, जो 6 सितंबर, 2023 को भौतिक मोड में श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर के सचिव श्री पंकज कुमार ने की। श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) के साथ-साथ डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, उत्तराखंड सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के संबद्ध कार्यालयों के अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) द्वारा परियोजना हेतु वित्त प्रवाह की स्थितिपर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई और बताया गया कि निर्माण पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं। किशाऊ बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना की डीपीआर के अद्यतनीकरण की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश के लिए, सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी ने बताया कि बांध स्थल क्षेत्र कमजोर नींव की चट्टान से ढका हुआ है जिसमें शेल/चूना पत्थर/डोलोमाइट के पतले बैंड हैं। रेणुकाजी बांध जलाशय में बड़े अवसादन की संभावना भी चिंता का विषय है क्योंकि बड़े जलाशय क्षेत्र पर चट्टानों की नरम संरचना का कब्जा है। इस संबंध में, आवश्यक भूवैज्ञानिक जांच और संबंधित अध्ययन करने के लिए सीडब्ल्यूसी की सलाह पर एचपीपीसीएल द्वारा भूवैज्ञानिकों के समूह का गठन किया गया था।

## पुनात्सांगछू-I एचईपी (6x200 मेगावाट) भूटान, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की 31वीं तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) (चरण I और II) की बैठक

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी और सह-अध्यक्ष-टीसीसी, और श्री एम.ए.के.पी. सिंह, सदस्य (हाइड्रो), सीईए और अध्यक्ष-टीसीसी ने भूटान के पुनातसांगचू-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (पीएचईपी-I) के लिए सितंबर 12,2023 को, हाइब्रिड मोड में 31वीं टीसीसी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आरजीओबी और पीएचपीए-I पहले चरण के निर्णयों के बाद, श्री सिब्बल और श्री सिंह ने टीसीसी सदस्यों के साथ, प्रस्तावित बोरहोल स्थानों पर 27 सितंबर, 2023 को एक संयुक्त साइट का दौरा किया। टीसीसी की बैठक 28 सितंबर, 2023 को आरकेपीओ होटल, लोबेसा में श्री सिंह और श्री सिब्बल की अध्यक्षता में हुई। प्रमुख सीडब्ल्यूसी प्रतिनिधियों ने भाग

लिया, और दाशो छेवांग रिनज़िन, अधिकारियों ने आभासी रूप से भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप बाद की साइट यात्रा और टीसीसी बैठक के दौरान बोरहोल विवरण को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। एमडी (डीजीपीसी) ने आरजीओबी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सहयोगात्मक प्रयासों का उद्देश्य पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना की सफलता को बढ़ाना है।

## उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों के लिए कैबिनेट नोट की प्रगति की समीक्षा के लिए 27.09.2023 को विशेष सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एफएम विंग, डीओडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूसी मुख्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बैलेंस वर्क्स के प्रस्ताव को मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए आगे की राह पर चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।

## मयूराक्षी बांध परियोजना और फुबरी बांध की लागत हिस्सेदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समिति की दूसरी बैठक

उपरोक्त समिति की दूसरी बैठक 01.09.2023 को सीडब्ल्यूसी के समिति कक्ष, दूसरी मंजिल (एस), सेवा भवन, नई दिल्ली में श्री नवीन कुमार, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी और समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में सीडब्ल्यूसी, बिहार सरकार, झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी शामिल हुए।

मयूराक्षी बांध परियोजना के संबंध में आगे बढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार से डेटा/विवरण मांगा गया था। फुलबारी बांध की लागत साझा करने के संबंध में, यह सहमति हुई कि 2019 में एचएसओ, सीडब्ल्यूसी द्वारा किया गया जल उपलब्धता अध्ययन स्वीकार्य है और बिहार सरकार को मांग का सतत अनुकरण अध्ययन करने के लिए कहा गया था।

# सीडब्ल्यूसी की अन्य गतिविधियाँ

## हथनीकुंड और ओखला बैराज के बीच पहुंच के लिए यमुना नदी के संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन हेतु समिति की पहली बैठक

हथिनीकुंड और ओखला बैराज के बीच यमुना नदी की पहुंच के लिए संयुक्त बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 04.09.2023 को हाइब्रिड मोड में समिति की पहली बैठक ली। सीडब्ल्यूसी, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे, एनआरएससी, आईएमडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली, डीडीए, हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सीपीडब्ल्यूडी ने बैठक में भाग लिया।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष ने मामले से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की। इसके लिए आवश्यक विभिन्न अध्ययनों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रत्येक अध्ययन के लिए डेटा की आवश्यकता और उसे उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण की भी पहचान की गई। यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध डेटा दस दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, ऊपरी यमुना पहुंच के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा डीटीएम अध्ययन जल्दी पूरा किया जाएगा और पहले ही पूरे हो चुके हिस्से का डेटा तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में निर्णय के अनुसार विभिन्न संबंधित अधिकारियों/विभागों को अध्ययन पर कार्य करने का निर्देश दिया गया।

## केंद्रीय जल आयोग और मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

मध्य प्रदेश के धार जिले में करम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए डिजाइन समीक्षा परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के बीच 11.09.2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा और डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ केंद्रीय जल आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एमओयू के अनुसार, सीडब्ल्यूसी डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश की डिजाइन इकाई द्वारा जारी किए गए डिजाइन और ड्राइंग की समीक्षा/ परीक्षण करेगा और बांध की पिछली विफलता/रिसाव के आधार पर सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, सुझाएगा।

## अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ वार्षिक संवाद बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने बिहार में जल संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 01.09.2023 को सिंचाई भवन, पटना में श्री चैतन्य प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के साथ वार्षिक संवाद बैठक की।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति, सामने आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के संभावित तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

जल-मौसम विज्ञान (हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल) डेटा साझाकरण पर केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार और जल संसाधन विभाग, बिहारसरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष डेटा साझा करने पर सहमत हुए जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार होगा।

## अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ वार्षिक संवाद बैठक

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने महाराष्ट्र में जल संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और जल संसाधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सीडब्ल्यूसी और महाराष्ट्र द्वारा किए जा रहे कार्यों में तालमेल बढ़ाने के लिए 08.09.2023 को मंत्रालय, मुंबई में श्री दीपक कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ वार्षिक संवाद बैठक की।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति और गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता वाले मुद्दों, बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने सीडब्ल्यूसी द्वारा की जा रही या परिकल्पित नई पहलों जैसे कि विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल भविष्यवाणी, बाढ़ मॉडलिंग आदि पर भी प्रकाश डाला।

बैठक में केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति और गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता वाले मुद्दों, बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने सीडब्ल्यूसी द्वारा की जा रही या परिकल्पित नई पहलों जैसे कि विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल भविष्यवाणी, बाढ़ मॉडलिंग आदि पर भी प्रकाश डाला।

## स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट लैब (एसएलसीआर) पर संयुक्त संचालन समिति (जेएससी)

स्वच्छ नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट लैब (एसएलसीआर) पर संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) ने 26 सितंबर, 2023 को वाराणसी में अपनी उद्घाटन बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय पक्ष ने की, जिसका नेतृत्व केंद्रीय जल आयोग के सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और सदस्य (आरएम) ने किया, और डेनिश पक्ष की अध्यक्षता नई दिल्ली में डेनमार्क के राजनीतिक और आर्थिक अनुभाग के दूतावास ने की। सीडब्ल्यूसी, सीपीसीबी, एनएमसीजी, सीजीडब्ल्यूबी, यूपीपीसीबी, यूपीजेएन, आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले जेएससी के सदस्यों और डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इसका उद्देश्य हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोगात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाना था।

संयुक्त संचालन समिति की बैठक में चर्चा आईआईटी-बीएचयू की एक व्यापक रिपोर्ट पर केंद्रित थी, जिसमें वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए डेनमार्क द्वारा वित्त पोषित स्मार्ट प्रयोगशाला की योजनाओं का विवरण दिया गया था। एसएलसीआर की स्थापना डेनमार्क से वित्त पोषण के साथ की गई थी। आईओ टी-सक्षम जल निगरानी प्रणाली और भूभौतिकीय सर्वेक्षण सहित चार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इस परियोजना में एक कीचड़ उपचार प्रणाली, उभरते प्रदूषकों के परीक्षण के लिए एक भौतिक प्रयोगशाला और समग्र वरुणा नदी का कायाकल्प शामिल है। परियोजना समीक्षा समिति के अपडेट, विश्लेषणात्मक निगरानी तंत्र, डेटा प्लेटफ़ॉर्म और क्षमता निर्माण प्रयासों पर चर्चा की गई।

## पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की 5वीं बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीएंडडब्लूएम के पुन:अभिमुखीकरण के लिए कार्य समूह की 5वीं बैठक 21 सितंबर, 2023 को सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी-डब्ल्यूएम पर चर्चा की गई और ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए पीएमओ, सीडब्ल्यूसी; पीएओ, सीडब्ल्यूसी और पीओएमआईओ, सीडब्ल्यूसी से अंतिम इनपुट शामिल किए गए।

## प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना के संचालन के लिए एमआई स्टेट विंग, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर और केंद्रीय जल आयोग के बीच समझौता ज्ञापन

29 सितंबर, 2023 को 'सिंचाई जनगणना' योजना के तहत वृहत और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं की पहली जनगणना आयोजित करने के लिए लघु सिंचाई (सांख्यिकी) विंग और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन स्थापित किया गया था। इसमें शामिल गतिविधियों में एमएमआई जनगणना के लिए मसौदा कार्यक्रम, निर्देश मैनुअल और परिचालन दिशानिर्देश शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के लिएपायलट परीक्षण और संशोधन सुझाव, जल संसाधन परियोजनाओं से संबंधित इंजीनियरिंग पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं और डेटा जांच और सत्यापन के बाद एक व्यापक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना होगा। इस सहयोग का उद्देश्य एमएमआई परियोजनाओं की जनगणना का सफल निष्पादन सुनिश्चित करना है।

## सिंचाई जनगणना योजना के तहत 7वीं एमआई जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना, एमएमआई परियोजनाओं की पहली जनगणना और झरनों की पहली जनगणना के लिए अनुसूचियों और परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना

25 सितंबर, 2023 को 7वीं लघु सिंचाई (एमआई) जनगणना, जल निकायों की दूसरी जनगणना, प्रमुख और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाएं, और स्प्रिंग्स की पहली जनगणना के कार्यक्रम और परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना 'सिंचाई जनगणना' के तहत आयोजित इस बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त इनपुट की सावधानीपूर्वक जांच की गई और चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा से उपरोक्त जनगणनाओं के लिए कार्यक्रम और परिचालन दिशानिर्देशों से संबंधित सुझावों और संशोधनों पर आपसी सहमति बनी।

## अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने अध्यक्ष, पीसीटीए और आईसीआईडी के उपाध्यक्षों के साथ बैठक में भाग लिया

आईसीआईडी के उपाध्यक्ष पीसीटीए के तहत रणनीति विषयों, जैसे ज्ञान, बेसिन, योजनाएं और ऑन-फार्म के सह-थीम नेता हैं, और इन रणनीति विषयों के तहत, पीसीटीए को रिपोर्ट करने वाले आईसीआईडी डब्ल्यूजी का आयोजन किया जाता है। पीसीटीए बैठकों के दौरान, प्रत्येक विषय के सह-विषय नेता एक संश्लेषित रिपोर्ट के रूप में संबंधित विषय के तहत कार्य निकायों के समग्र प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हैं।

श्री कुशविंदर वोहरा, (सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और आईसीआईडी के उपाध्यक्ष) ने प्रत्येक प्रभारी उपाध्यक्ष के कार्य समूहों पर चर्चा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए 27 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक में भाग लिया।

# आईसीआईडी की 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और 74वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक (आईईसी) की तैयारी के लिए गठित उप-समितियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा

सिंचाई और जल निकासी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसीआईडी) 2-8 नवंबर, 2023 के दौरान विशाखापत्तनम (ए.पी.) में सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीआईडी) की 25वीं कांग्रेस का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में लगभग 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 1200 प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए, 11 उप-समितियों का गठन किया गया है, जिसमें सीडब्ल्यूसी और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हैं।

इस संबंध में, श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी/अध्यक्ष आईएनसीआईडी ने स्थिति का जायजा लेने और व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए 4 सितंबर, 2023 को हाइब्रिड मोड में सीडब्ल्यूसी, आईसीआईडी और एपी सरकार के अधिकारियों को शामिल करने वाली सभी ग्यारह उप-समितियों के साथ एक बैठक बुलाई। वित्त, तकनीकी, पंजीकरण, मीडिया और प्रचार, परिवहन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाएं और प्राथमिकता दें। इस संबंध में विभिन्न समय-सीमाओं को अंतिम रूप दिया गया।

## जलाशय निगरानी

सीडब्ल्यूसी साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.09.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 129.669 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 73% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 158.744 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 140.472 बीसीएम था। इस प्रकार, 29.09.2023 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 82% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 92% है।

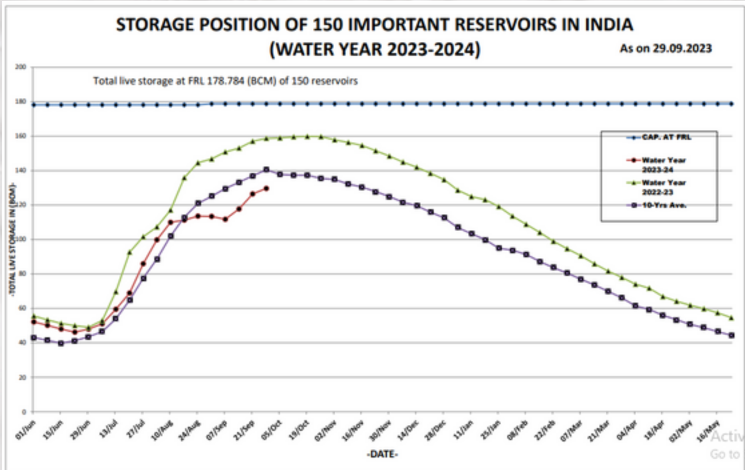


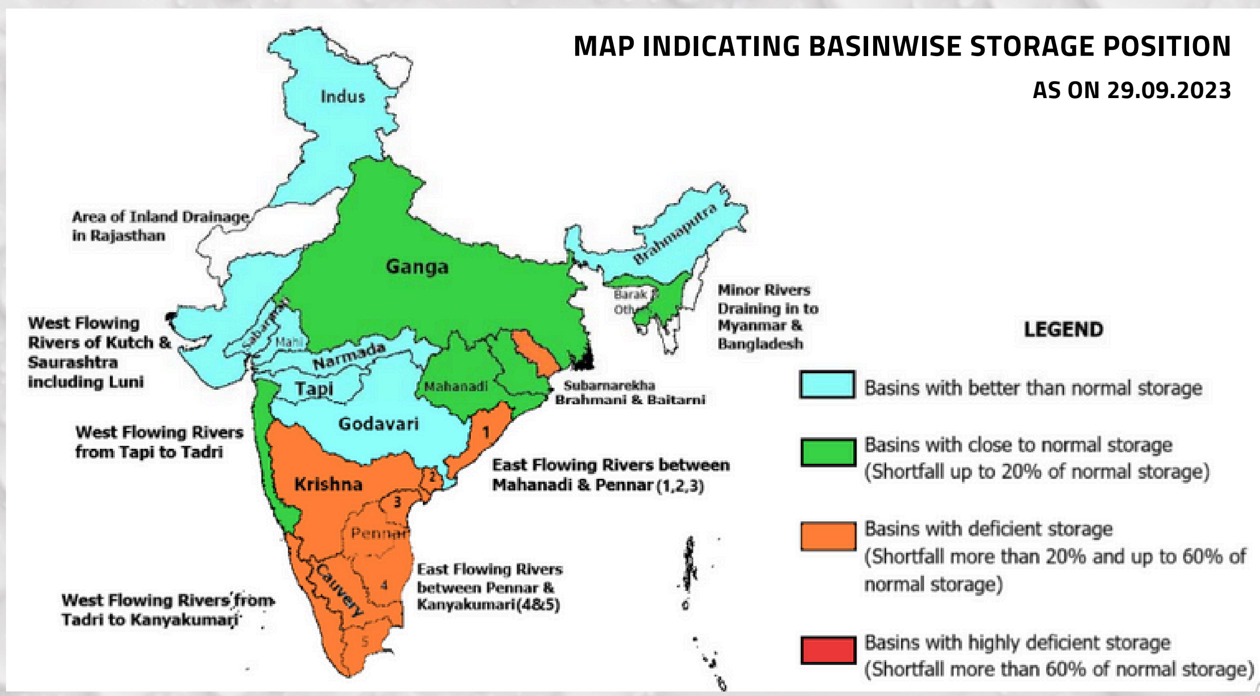

# देश में बाढ़ की स्थिति - सितम्बर 2023

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 01 मई से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, कुल 5945 (4406 स्तर+1539 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 5615 (4195 स्तर+1420 प्रवाह) पूर्वानुमान अनुमेय सीमा के भीतर थे, सटीकता 94.44 प्रतिशत थी। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सितंबर माह में 23 रेड बुलेटिन (अत्यधिक बाढ़ की स्थिति के लिए) और 85 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

## 01.05.2023 से 30.09.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

### चरम बाढ़ की स्थिति

04 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

| क्र.सं. | राज्य | जिला | नदी | स्टेशन | अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | से | तक |
| 1 | एनसीटी दिल्ली | उत्तरी दिल्ली | यमुना | दिल्ली रेलवेब्रिज | 12/07/2023 | 15/07/2023 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | बदायूँ | गंगा | कछलाब्रिज | 14/07/2023<br>16/07/2023<br>29/07/2023<br>18/08/2023 | 15/07/2023<br>22/07/2023<br>01/08/2023<br>20/08/2023 |
| 3 | असम | शिवसागर | दिखो | शिवसागर | 17/07/2023<br>11/08/2023 | 17/07/2023<br>12/08/2023 |
| 4 | तेलंगाना | कुमुराम भीम | वर्धा | सिरपुर नगर | 24/07/2023<br>29/07/2023 | 24/07/2023<br>29/07/2023 |

55 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

### गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड,महाराष्ट्र, , राजस्थान, और गुजरात में 75 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, ओड़िशा, झारखंड और गुजरात में 58 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

### सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 44 एफएफ स्टेशन पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

### सीमा-रेखा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 76 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्राप्त हुआ।

# 30.09.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

| क्रमांक | योजना/घटक का नाम | बजट अनुमान (2023-24) | व्यय | व्यय (%में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस) | 162.130 | 79.6144 | 49.11% |
| 2 | जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी) | 20.000 | 0.8337 | 4.17% |
| 3 | बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) | 20.310 | 5.1238 | 24.63% |
| 4 | निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी) | 11.000 | 1.5376 | 13.98% |
| 5 | राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी) | 31.58 | 9.3733 | 29.68% |

# "स्वच्छता ही सेवा " अभियान

एम.ई.आर.ओ., भुवनेश्वर

प्रबोधन मध्य संगठन, नागपुर

एम.टी.बी.ओ., गांधीनगर

के .जी.बी.ओ., हैद्राबाद, पहले

के .जी.बी.ओ., हैद्राबाद, बाद मे

के .जी.बी.ओ., हैद्राबाद, पहले

के .जी.बी.ओ., हैद्राबाद, बाद मे

यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली

# गैलरी

केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे हिन्दी पखवाड़े का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में सेवारत गैर-तकनीकी अधिकारियों के लिए 25 से 29 सितंबर 2023 तक एनडब्ल्यूए, पुणे में पांच दिवसीय "प्रबंधन विकास कार्यक्रम" शुरू हुआ।

दिनांक 18.09.2023 को राज्य अतिथि गृह, भुवनेश्वर में माननीय राज्य मंत्री (जल शक्ति एवं जनजातीय मामले) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए.

सरयू नहर परियोजना पीएच-III न.प्र. का प्रथम अनुश्रवण दौरा। वर्ष 2023-24 के लिए एम एंड ए लखनऊ द्वारा 15.09.2023 को आयोजित किया गया था।

दिनांक 18.09.2023 को माही एवं तापी बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, गांधीनगर में विश्व जल निगरानी दिवस- 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया | कार्यक्रम में आदर्श निवास कुमार शाला एवं आदर्श निवास कन्या शाला, सेक्टर- 8, गांधीनगर के विद्यार्थियों के साथ जन-जागरूकता रैली का आयोजन किया गया

11 सितंबर से 15 सितंबर, 2023 तक राष्ट्रीय जल अकादमी में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा (सीडब्ल्यूईएस) के जेएजी स्तर के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

**केंद्रीय जल आयोग**

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

**संपादक मंडल**

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनिलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

**अभिकल्प एवं प्रकाशन**

**जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय**
**केन्द्रीय जल आयोग**

**द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066**
**ई-मेल: media-cwc@gov.in**